

एक-चौथाई सदी की पारी के बाद जननायक की विदाई

नवीन पटनायक कुछ दिन और सत्ता में रह पाते तो उनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल देश में सबसे ज्यादा होता। इसके बावजूद लगातार 24 साल तक उन्होंने एकछत्र राज किया। हालांकि, इस बार के लोकसभा चुनाव के साथ कराए गए ओडिशा विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी बीजू जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिस पार्टी को नब्बे के दशक में राज्य की राजनीति में पैर रखने की जगह बीजद ने दी थी, उसी ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। राज्य में अब भाजपा पहली बार सरकार बनाने जा रही है। उसे विधानसभा की 78 सीटें मिली हैं। वहीं आम चुनाव में लोकसभा की कुल इक्कीस सीटों में से बीस सीटें भाजपा को मिली हैं। वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा है कि लगातार पांच बार विधानसभा चुनाव जीतने और चौबीस साल तक निष्कट राज करने वाले नवीन पटनायक अपने एक अन्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए। बीजद को 51 विधानसभा सीटों पर सफलता जस्टिस मिली मगर लोकसभा की एक भी सीट बीजद नहीं जीत सकी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजद ने 12 व भाजपा ने आठ सीटें जीती थी। हालांकि, राजनीति के पुराने खिलाड़ी नवीन पटनायक को इस बात का बखूबी अहसास था कि भाजपा उन्हें सत्ता से विस्थापित कर सकती है। फलतः उन्होंने अपने अंतिम कार्यकाल में भाजपा की काट के लिए सांस्कृतिक राजनीति का सहारा लेना शुरू कर दिया था। वे महसूस कर रहे थे कि ओडिशा के छोटे शहरों के युवाओं का रुझान भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है। अब तक लोक कल्याण योजनाओं को अपनी राजनीति की धार बनाने वाले नवीन पटनायक ने अयोध्या की रणनीति के मुकामले में श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास में एक हेरिटेज कॉरिडोर को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। राज्य के अनेक प्राचीन मंदिरों को जीर्णोद्धार के जरिये नये सिरे से निरखारा गया। इसके अलावा हाल ही में पहले विश्व उडिया भाषा सम्मेलन आयोजित करके साहित्य व संस्कृति कर्मियों को जोड़ने का प्रयास किया गया। दरअसल, राज्य में बदलती राजनीतिक बयार के मद्देनजर नवीन पटनायक ने युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रमों को तरजीह दी। लोकप्रिय कल्याण कार्यक्रमों से इतर पटनायक ने बीजेपी की तरफ बढ़ रहे युवाओं को साथ जोड़ने के लिये ओडिशा को देश के खेलों की राजधानी बनाने का प्रयास किया। उन्होंने उन खेलों को तरजीह दी जो क्रिकेट की सुनामी में हाशिये पर जा रहे थे। पटनायक सरकार ने हॉकी की राष्ट्रीय पुरुष व महिला हॉकी टीम को प्रायोजित किया। इसके अलावा पर्याप्त खेल संरचना के विस्तार के साथ ही राज्य में दो विश्व हॉकी कप श्रृंखला आयोजित की गई। राज्य में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की असंतोषजनक स्थिति के मद्देनजर अस्पतालों का आधुनिकीकरण, स्कूलों की संरचना में बदलाव, बस सेवाओं में सुधार के प्रयास पिछले कुछ समय में किए गए।

किन नवनिर्वाचित सांसदों पर देश की रहेगी नजर



आर.के. सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, संभकार और पूर्व सांसद हैं)

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उनका गहन विश्लेषण भी हो रहा है, पर इस प्रक्रिया के दौरान उन तीन नतीजों पर भी देश को गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा जहां से देश के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले तीन उम्मीदवार जीत गए हैं। पंजाब की खडूर साहिब और फरीदकोट लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम सिख राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बदलाव और

अमृतपाल सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को आसानी से मात दे दी। यह लोकसभा सीट पंजाब में भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। उनकी गैरमौजूदगी में उनके माता-पिता उनके लिए प्रचार कर रहे थे। खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र में अमृतसर-तरन-पट्टी के क्षेत्र शामिल हैं, जो जरनैल सिंह भिंडरावाले का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। यह सीट सिखों का गढ़ मानी जाती है। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अपने कार्यालयों में भिंडरावाले के पोस्टर भी लगाए थे। उन्होंने भी ड्रग संस्कृति को समाप्त करने और बंदी सिखों को रिहा कराने का वादा किया।

पंथिक राजनीति के पुनरुत्थान का संकेत देते हैं। कट्टरपंथी प्रचारक अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब से और इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह ने फरीदकोट से जीत हासिल की है, दोनों ही निर्दलीय प्रत्याशी थे। अमृतपाल सिंह खालिस्तान के पक्ष में बोलते रहे हैं। इसी तरह से जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से इंजीनियर राशिद का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराना अपने आप में सामान्य घटना नहीं है। राशिद पाकिस्तान परसत रहे हैं और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

पर पहले बात कर लें अमृतपाल सिंह की। उन्हें पिछले साल राष्ट्रीय सुशासन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर असम के डिब्रूगढ़ में जेल में रखा गया था। सरबजीत सिंह की जीत ने भी साबित कर दिया है कि सिख अभी तक ऑपरेशन ब्लूस्टार और उन भयानक सिख विरोधी दंगों को भूलें नहीं हैं। सच में फरीदकोट ने बड़ा आश्चर्यजनक नतीजा दिया जब सरबजीत सिंह ने हवाई लोकप्रिय अभिनेता करमजीत अमनोल को हरा दिया, जबकि उनका फरीदकोट में कोई बड़ा नेटवर्क नहीं था। जब इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल के कारण सरबजीत सिंह के पिता को गिरफ्तार किया गया था, वे तब मात्र 6 साल के थे। उन्होंने बारहवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वे पहले भी कई चुनावों में किस्मत आजमा चुके हैं। उन्होंने 2007 में बम्बाला जिले के भदौर से पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ा और उन्हें केवल 15,702



वोट मिले। उन्होंने 2004 में बटिंडा लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा और असफल रहे। उन्हें 1,13,490 वोट मिले। 2009 और 2014 में उन्होंने फिर से क्रमशः बटिंडा और फतेहगढ़ साहिब (अरक्षित) को निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। सरबजीत सिंह की मां, बियल कौर और उनके दादा, सुच्चा सिंह पूर्व में लोकसभा के लिए चुने गए थे। सरबजीत सिंह इस बार तो चुनाव लड़ने के मूढ़ में नहीं थे। उनसे जड़ बहुत लोगों ने चुनाव लड़ने की गुंजायिश की तो वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। वे अपनी कैम्प में सिखों के ससलों के अलावा फरीदकोट में नशे की बढ़ती समस्या से लड़ने का वादा कर भी रहे थे। फरीदकोट के लिए कहा जाता है कि यह जिला नशाखोरी की चपेट में पूरी तरह से आ चुका है।

अमृतपाल सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को आसानी से मात दे दी। यह लोकसभा सीट पंजाब में भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। उनकी गैरमौजूदगी में उनके माता-पिता उनके लिए प्रचार कर रहे थे। खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र में अमृतसर-तरन-पट्टी के क्षेत्र शामिल हैं, जो जरनैल सिंह भिंडरावाले का प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। यह सीट सिखों का गढ़ मानी जाती है। अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने अपने कार्यालयों में भिंडरावाले के पोस्टर भी लगाए थे। उन्होंने भी ड्रग संस्कृति को समाप्त करने और बंदी सिखों को रिहा

कराने का वादा किया।

दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में कई उलटफेर देखने को मिले। ऐसी ही जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट है। यहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। इंजीनियर अब्दुल राशिद शेर से हार का सामना करना पड़ा। इंजीनियर अब्दुल राशिद शेर फिलहाल उसी तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बंद हैं। राशिद शेर को साल 2019 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के केस में गिरफ्तार किया था। अमृतपाल की तरह से उन्होंने भी जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा। अब सवाल यह है कि इन संदिग्ध छवि वाले उम्मीदवारों के लोकसभा में पहुंचने से क्या संदेश गया? पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के कथित असर वाले पंजाब में अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह की जीत से साफ है कि इनके नेताओं को यह जवाब तो देना ही होगा कि राज्य में देश विरोधी ताकतें कैसे अपने पैर जमा रही हैं? पंजाब में आप की नीतियों को लेकर तो जनता में खासा गुस्सा दिखाई दिया। राज्य की जनता आप के नेता अरविंद केजरीवाल और राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान से नाराज है। आप ने पंजाब में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उसे उम्मीद थी कि राज्य में उसकी सरकार है, ऐसे में वह कम से कम राज्य की 13 सीटों में से 10 पर तो जीत हासिल करेगी। हालांकि, उसे तीन सीटों से ही संतोष करना पड़ा। होशियारपुर, आनंदपुर

साहिब और संगरूर को छोड़कर बाकी की सभी 10 सीटों पर आप को हार का सामना करना पड़ा।

आप को दिल्ली में भी मुंह की खानी पड़ी। आप ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इसके तहत दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली के तौर पर चार सीटें उसके खाते में आईं। यह सब सीटें आप हार गईं। आप को 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी एक ही सीट पर जीत नहीं मिली थी। इसी प्रकार कांग्रेस भी अपनी तीनों सीटें हार गईं। इसमें हट्टुकड़े-टुकड़े गैंगू के कन्हैया कुमार की सीट थी। यह दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस की अ-लोकप्रियता को दर्शाता है।

एक बार फिर इंजीनियर राशिद पर लौटते हैं। राशिद को वर्ष 2004 में श्रीनगर में आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे तीन महीने और 17 दिनों के लिए जेल में रखा गया था। उस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था। बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने मानवीय आधार पर उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए। उन्हें अगस्त 2019 में कश्मीर के सभी मुख्यधारा के राजनेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। तब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। राशिद लगातार देश और हिन्दू विरोधी हरकतें करने से बाज नहीं आते। 8 अक्टूबर 2015 को इंजीनियर राशिद पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अंदर भाजपा विधायकों द्वारा हमला किया गया था, क्योंकि उन्होंने सरकारी सफ़्टवेयर हाउस के लॉन में गोमारा परोसने वाली एक पार्टी की मेजबानी की थी।

जाहिर है, उर्पुक्त तीनों नव निर्वाचित सांसदों की गतिविधियों पर देश को पैनी नजर रखनी होगी। मेरी तो यही शुभकामना है कि ये देश की बदली परिस्थिति में अपना चाल-चरित्र और चेहरा बदलें वरना देश की राष्ट्रवादी सरकार की सख्त कार्रवाई को भुगतने को तैयार रहें।

एक त्रुटिपूर्ण रणनीति का बेढंगा निपटान



रमेश इन्दर सिंह

लेखक पंजाब के गृह सचिव रहे हैं

देश के लिए वर्ष 1984 एक विध्वंसक साल रहा। इसमें घटित बड़े प्रसंग गौरतलब हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, प्रधानमंत्री की हत्या और सिख विरोधी नरसंहार इस एक वर्ष ने राष्ट्र के आंतरिक विमर्श और इतिहास का जिस प्रकार निर्धारण किया उतना शायद आजादी के उपरांत किसी अन्य साल ने नहीं किया। 40 साल गुजरना भी इसके आघात की टीस नहीं भर पाया। प्रभावित हुए लोगों को न्याय न मिलने की धारणा और त्रासदी की चुभन अभी भी सालती है। तमाम संबंधित पक्षों झूठे राजनीतिक तत्व, सरकार के इशारे पर काम करने वाले, आतंकवादी और नरसंहार में लिप्त भीड़-कौड़ी जवाबदेही तय करने के लिए यदि सत्य एवं सुलहकारी कोई आयोग बनाया गया होता तो शायद न्यायिक प्रक्रिया एवं मान-मनौबल से अंततः आहत भावनाओं के मामले का संतोषप्रद समाधान हो पाता।

क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार करने से बचा जा सकता था? तत्कालीन केंद्रीय सरकार आतंकवाद को खत्म के वास्ते इस कार्रवाई को बतौर एक अवशर्भावो उपाय पेश करती रही। उस वक्त हथियारबंद विद्रोहियों ने पूरे स्वर्ण मंदिर परिसर पर कब्जा कर रखा था और हथियारों से लैस चौकियां बना डालीं और संवैधानिक रूप से स्थापित राष्ट्र-नीति की वैधता को चुनौती देने को उद्यत थे। आम दलील अक्सर यह आती है- यदि स्वर्ण मंदिर परिसर में सशस्त्र विद्रोही किलेबंदी न करते तब क्योंकि सेना लगाने की जरूरत पड़ती।

आस्थावानों की धारणा किंतु इससे विपरीत है। ऑपरेशन ब्लू स्टार को सिखों के सबसे पवित्रतम स्थल को अपमानित करने की एक पूर्व निर्धारित योजना के रूप में देखा जाता है, जिसके पीछे मकसद था ध्रुवीकरण पैदा करके



कुछ महीने बाद होने वाले आम चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाना। इसको समझने के लिए आठवीं लोकसभा के चुनाव प्रचार में जारी विज्ञापनों में ध्रुवीकरण करती इबारत बांचें तो झहझका देश की सीमा अंततः आपकी दहलीज तक आ जाएगी। या सिख चालक वाली टैक्सि दिखाकर संलग्न किया सवाल : हक्या आप इस टैक्सि में सुरक्षित महसूस करेंगे।

विध्वंसक घटनाएं अक्सर उद्देश्य को ढांप देती है, विशेषकर आस्था के मामले में। ब्लू स्टार के मामले में अब कुछ तथ्य पूरी तरह स्थापित एवं किंतु-परंतु से इतर स्पष्ट हैं। संक्षेप में घटनाक्रम बताएं तो, अकाली दल ने 4 अगस्त, 1982 को अपनी दस मांगों को लेकर मोर्चा लगाने का ऐलान किया। इनमें धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और अंतरराज्यीय विवाद

संबंधी मुद्दे थे। इसके लिए प्रदर्शनकारी रोज शांतिपूर्ण ढंग से गिरफ्तारियां देते थे। जून 1984 तक, लगभग 1 लाख 70 हजार कार्रकांतों ने गिरफ्तारी दी। पंजाब के लगभग 12000 गांवों में शायद ही कोई ऐसा होगा जहां से लोगों ने इस आंदोलन में भाग न लिया हो। अकालियों को अपने अनाड़ीपन में लगता था कि यदि वे जेलें भर देंगे तो केंद्र सरकार उनकी मांगों मानने को मजबूर हो जाएगी। लगभग दो साल तक इस आंदोलन में कोई 26 मौके ऐसे आए जब समझौते के प्रयास सिरे चढ़ते महसूस हुए, कुछ में प्रधानमंत्री और विपक्षी नेताओं ने भी भाग लिया। कम से कम दो अक्सर ऐसे रहे जब सन्मति पूरी तरह बन गई लेकिन केंद्र सरकार ऐन मौके पर पीछे हट गई। लगता है सरकार ने राजनीतिक हल न निकालने का मन बना लिया

था और कैबिनेट की उप समिति ने मई 1984 में समस्या का सैन्य समाधान करना चुना। प्रणव मुखर्जी द्वारा पेश चेतावनी को किनारे करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा : हथप्रणव, मुझे नतीजों के बारे में ज्ञान है। यह निर्णय बदला नहीं जा सकता। फिर 25 मई को सेना प्रमुख को सेना को अमृतसर पहुंचाने के आदेश दिए गए हालांकि दिखावे के तौर पर 29 मई को अकालियों के एक प्रतिनिधिमंडल से केंद्रीय मंत्रियों का समझौता वार्ता का क्रम जारी रहा। इसमें आम सहमति बन भी गई लेकिन बाद में केंद्रीय मंत्री अपनी बात से यह कहकर पीछे हट गए : हथप्रणव नहीं मान रहें।

पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल बीडी पांडे को सेना बुलाने के लिए अर्जी देने के कहा गया और इसके वास्ते औपचारिक आदेश पंजाब के

गृह सचिव ने 2 जून को जारी किए। सेना ने स्वर्ण मंदिर और अन्य 42 गुरुद्वारों पर कार्रवाई की। राज्यपाल पांडे ने सैन्य अभियान न किए जाने की गृहार लगाई और बाद में पुष्टि की कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजनीतिक हल नहीं चाहती थीं। उधर जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ भी सरकार की प्रस्तावित वार्ताएं दो बार स्थगित हुईं जिसमें एक सीधी राजीव गांधी से होनी थी। तब जरनैल सिंह भिंडरावाले ने अपने समर्थकों से कहा : हथप्रणव भले जारी रखो, लेकिन अपनी तैयारी भी पूरी रखो। और यह तैयारी थी सशस्त्र आंदोलन की, जो अकाली दल के शांतिपूर्ण मोर्चे के समानांतर चली हुई थी।

विद्रोही इसे हथप्रणव ही लड़ाई करार दे रहे थे। उनके लिए, हिंसा पुलितिया जबर की प्रतिक्रिया थी और राजसत्ता से संवाद का एक अन्य ढंग भी, उनके अपने तरीके का। चूक विद्रोहियों को संवैधानिक रूप से वैधता प्राप्त नहीं होती इसलिए वे विद्वान मार्क जुर्गेन मेयर के शब्दों में हथप्रणव प्रदत्त अधि-नैतिकता को अपनी स्वीकार्यता का आधार बताते हैं। तत्पश्चात हिंसा उत्तरोत्तर बढ़ती गई। पाकिस्तान ने विद्रोहियों को प्रशिक्षण और हथियार देकर अपना खेल शुरू कर दिया। राज्य व्यवस्था यद्यपि सुस्त न थी तो भी निष्प्रभावी लगने लगी। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर मशीनगन सहित हथियारबंद किलेबंदी होने लगी। तत्कालीन पुलिस प्रमुख प्रीतम सिंह भिंडर की मांगें तो अंदर पहुंचाए जाने वाले हथियारों की जल्दी इसलिए नहीं की गई क्योंकि जून से दो माह पहले तक ऐसा न करने का मौखिक आदेश हाइडर सेह था, लिहाजा कार सेवा के ट्रकों की तलाशी नहीं ली जाती थी। सेना ने 3 जून की रात को स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया। सेना ने विद्रोहियों से समर्पण करवाने हेतु वार्ता का प्रयास नहीं किया।

विद्रोहियों का नेतृत्व मेजर जनरल शबेग सिंह के हाथ में था जोकि भारतीय सैन्य अकादमी में उस वक्त प्रशिक्षक थे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार में सैनिकों के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार वहां कैडेट थे। दोनों एक-दूसरे को भलाभाति जानते थे। यदि उनकी आपस में बातचीत होती तो शायद इस खूनी त्रासदी को टाला जा सकता था। लेकिन यह

वह किंतु-परंतु है, जिससे इतिहास रचा होता है। फिर, चरमपंथियों ने लड़ाई की, पश्चिमी सैन्य कमान के जीओसी रहे ले. जनरल वीके नायर के शब्दों में : हथप्रणव उनको और कोई विकल्प नहीं दिया गया।

5 और 6 जून की मध्यरात्रि भयावह थी। अकाल तख्त, जो कि मुगल एवं अफगान आक्रांताओं के विरुद्ध सिख सार्वभौमिकता और सधर में ऐतिहासिक प्रतीक रहा है, वह खंडहर में तब्दील हो गया। सैन्य कार्रवाई में लगभग 330 सुरक्षाकर्मी और 780 सिविलियन मारे गए, जिनमें से श्रद्धालु भी शामिल थे जो स्वर्ण मंदिर के संस्थापक गुरु अर्जुन देव के शहीदी पर्व के अवसर पर इकट्ठा हुए थे। निशाने से चूके गोलों की वजह से परिसर के पश्चिमी सिरे से सटे निजी भवनों का बहुत नुकसान हुआ। लगभग 160 दुकानों और 15 घर तबाह हुए। लेकिन इस सबसे हासिल क्या हुआ? सेना ने कुछ सौ सशस्त्र लड़ाकों को मार गिराया, तथापि विजय विनाशकारी रही। ब्लू स्टार ने जातीय-राष्ट्रीय संघर्ष के बीज बो डाले, जिससे आगे और ज्यादा हिंसा जन्मी। देश अपने और अपनों के विरुद्ध लड़ने लगा, जिसमें कुछ सैनिकों ने हथियार सहित बैरकें छोड़कर विद्रोह कर दिया। विद्रोही तत्व जल्दी ही फिर से स्वर्ण मंदिर परिसर से काबिज हो गए और अप्रैल 1986 को परिसर से खालिस्तान की घोषणा कर दी। तत्पश्चात ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1 एवं 2 करने पड़े।

पंजाब की समस्याओं पर गौर करें तो बेढंगी रणनीति और खुरे तरीके से क्रियान्वयन वाला ऑपरेशन ब्लू स्टार एक भयंकर भूल साबित हुआ। राजीव-लोगोवाल समझौता कुछ आगे की राह दिखा सकता था किंतु इस पर भी अमल नहीं हुआ। पंजाब का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक दशक तक चली हिंसा के दौरान लगभग 30000 लोग मारे गए। देशभर में पहले पायदान पर रहा यह सूबा अधिकांश सामाजिक-आर्थिक पैमानों पर फिसलकर 15वें स्थान पर जा गिरा। जातीय-राष्ट्रीय आंदोलन भले ही खत्म हो गया किंतु विदेशों में बैठे एक धड़ें में अभी भी इसका स्पंदन जीवित है और यह भारत के लिए चिंताजनक है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्ष 17 अंक 97



विकेंद्रीकरण: हकीकत या महज दिखावा?

सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना चाहते हैं मगर इसके लिए सबसे पहले विकेंद्रीकरण की 'जन्मजात खामी' को दूर करना होगा। बता रहे हैं एम गोविंद राव

संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुए तीन दशक बीत चुके हैं। इतनी लंबी अवधि गुजरने के बाद भी पंचायती राज इकाइयों का वित्तीय सशक्तीकरण नहीं हो पाया है। ये दोनों संशोधन वर्ष 1993 में प्रभावी हुए थे मगर तब से स्थानीय निकायों का वित्तीय सशक्तीकरण महज दिखावा बन कर रह गया है। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही मान रहे हैं कि स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से सशक्त नहीं हो पाए हैं। वे अपने चुनावी घोषणापत्रों में भी इस विषय को उठाने लगे हैं।

सत्ताधारी दल पंचायतों को अधिक वित्तीय ताकत देना चाहता है, वहीं विपक्ष संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों का श्रेय ले रहे हैं। विपक्ष यह भी वादा कर रहा है कि वे अनुच्छेद 243 के अंतर्गत निहित प्रावधानों को उनकी मूल भावना के साथ लागू करने के लिए राज्यों को प्रेरित करने में सफल रहेगा। यद्यपि, दोनों ही पक्ष विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के महत्त्व को रेखांकित करते हैं मगर यह स्पष्ट नहीं है कि यह लक्ष्य किस तरह प्राप्त किया जा सकता है।

राजकीय विकेंद्रीकरण के संबंध में लागू होने वाला एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले दायित्व स्पष्ट होने चाहिए, उनके पास सार्वजनिक सेवाओं के वित्त पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए और वे सेवाएं मुहैया कराने वाले कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को नियुक्त करने एवं उनके कार्य प्रबंधन का अधिकार मिलना चाहिए। राजस्व के पर्याप्त एवं निश्चित स्रोत नहीं होने के कारण स्थानीय निकायों के वित्त आर्थिक संसाधन के अभाव में पूरे नहीं हो पाते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो यह स्पष्ट है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से शुरू हुई विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में गंभीर खामी है और वित्तीय तौर पर स्थानीय निकायों को दुरुस्त करने वाले किसी प्रयास को सबसे पहले इस खामी को दूर करना चाहिए।

स्थानीय निकायों को आवंटित कार्य भी स्पष्ट नहीं हैं। उन्हें राजस्व के पर्याप्त स्रोत नहीं दिए जाते हैं और इस कारण उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद पर निर्भर रहना पड़ता है। स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति भी राज्य सरकारें करती हैं। यद्यपि, संविधान संशोधन में उन्हें स्थानीय स्व-शासन का हिस्सा बनाने की बात कही गई है मगर इसकी जवाबदेही राज्य सूची की 7वीं अनुसूची में प्रविष्टि 5 के अंतर्गत राज्यों पर छोड़ दी गई है। यानी अनुच्छेद 243-जी और 243-डब्ल्यू ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को आर्थिक विकास योजनाएं तैयार करने एवं विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन (11वीं एवं 12वीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध योजनाओं सहित) का अधिकार देते हैं मगर कार्यों का वास्तविक निर्धारण पूरी तरह राज्य सरकारों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय निकायों के कार्य स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि इनमें राज्यों का हस्तक्षेप होता है।

वित्तीय संसाधनों से जुड़ी समस्या तो और भी कठिन है। अनुच्छेद 243-एच और 243-एक्स के अंतर्गत राज्यों को वित्त आयोग की नियुक्ति और राज्य विधानसभा को प्रत्येक पांच वर्षों पर राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन करना होता है। यह आयोग ग्रामीण एवं शहरी इकाइयों को करों एवं अनुदानों का विभाजन निर्धारित करता है। हालांकि, पिछले तीन दशकों का इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य तय प्रावधानों की अनदेखी करते हुए राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। जब कभी आयोग गठित होता है तो रिपोर्ट की गुणवत्ता क्रियान्वयन के योग्य नहीं होती है और राज्य इन रिपोर्टों को और इनके आधार पर उठाए गए कदमों को विधानसभा में नहीं रखते हैं। राज्यों के लिए ऐसा करना आवश्यक होता है। अब तक छह राज्य वित्त आयोगों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी मगर केवल कुछ ही राज्यों में ऐसा हो पाया है। राज्य स्थानीय निकायों को कुछ अस्थायी अनुदान दे रहे हैं मगर ये पर्याप्त होते हैं और उनको मिलाने पर भी अनिश्चितता बनी रहती है।

भारत में कार्यस्थलों पर कामगारों की आयु को लेकर समस्या देखने को मिल रही है। भर्ती एजेंसी रैंडस्टैंड द्वारा करीब 1,000 प्रतिभागियों पर किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक उनमें से 40 फीसदी को कार्यस्थल पर उम्र से संबंधित भेदभाव का सामना करना पड़ा या वे ऐसी घटनाओं के साक्षी बने। 55 वर्ष से कम आयु के 42 फीसदी प्रतिभागियों ने उम्र संबंधी भेदभाव का सामना किया या उसके गवाह बने जबकि 55 वर्ष से अधिक आयु के 29 फीसदी प्रतिभागियों के साथ ऐसा हुआ। सर्वेक्षण में शामिल 55 से कम उम्र के आधे से थोड़े अधिक प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें लगता है उनकी कदर की जाती है जबकि 55 से अधिक उम्र के 63 फीसदी कर्मचारियों ने ऐसा कहा। 35 वर्ष से कम आयु के 32 फीसदी प्रतिभागियों ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी कदर नहीं की जाती है या उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता। यह पूर्वग्रह रोजगार के विज्ञापनों में भी नजर आता है और यहां 61 फीसदी ने नौकरी के लिए आयु या अनुभव वर्षों को मानक बनाया है। इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों अग्रणी हैं। अन्य तरह के पूर्वग्रह भी आयु से संबंधी भेदभाव को बढ़ाते हैं। 42 फीसदी महिलाओं ने कहा कि उन्हें ऐसे भेदभाव का अनुभव होता है जबकि ऐसा महसूस करने वाले पुरुषों की तादाद केवल 37 फीसदी थी।

एक स्तर पर कार्यस्थल पर रिवर्स एजिस्म (युवाओं के साथ भेदभाव) चकित नहीं भी करता है क्योंकि भारत की जनॉकि की युवा है और देश की 65 फीसदी से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। हमारी पारंपरिक सामाजिक भावना भी बुद्धि और कार्रखिलियत को उम्र से जोड़कर देखने की रही है। परंतु व्यापक पैमाने पर देखें तो इस सर्वेक्षण में शामिल युवाओं जैसे कार्रखिलियत युवा जरूरी अनुभव प्राप्त करके रिवर्स एजिस्म की समस्या से निजात पा सकते हैं। वास्तव में चिंता इस बात को लेकर होनी चाहिए कि संस्थानों में आयु संबंधी भेदभाव की प्रवृत्ति घर घर गई है। दो अंतःसंबंधित तथ्य अगली पीढ़ी में कार्यस्थल को प्रभावित करेंगे पहला तो यह कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूनपीएफ) के अनुसार बुजुर्गों की दशकवार वृद्धि की दर 2011-21 के 35.5 फीसदी से बढ़कर 2021-31 तक 41 फीसदी हो जाएगी और आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी भी दोगुनी होकर 20 फीसदी से अधिक हो जाएगी। यूनपीएफ के अनुसार 2046 तक बुजुर्गों की आबादी 15 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों की आबादी को पार कर जाएगी।

अप्रत्याशित और तीव्र गति से उम्रदराज होती आबादी और बढ़ती जीवन प्रत्याशा के साथ अमर इस तथ्य को शामिल कर लिया जाए कि भारत में सेवानिवृत्ति की आयु विश्व स्तर पर प्रायः सबसे कम है तो इससे यही संकेत मिलता है कि जल्दी ही देश की आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसे सेवानिवृत्त लोगों का होगा जो अपनी बचत पर निर्भर होंगे। भारत में कंपनियों और सरकारी उपक्रमों में सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष के बीच है जबकि पूर्णकालिक निदेशकों के लिए यह अधिकतम 70 वर्ष एवं गैर कार्यकारी निदेशकों के लिए 75 वर्ष तक है। आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इटली जैसे विकसित देशों में यह आयु 66-67 वर्ष है। फ्रांस में जहां कामगार 50-60 वर्ष में सेवानिवृत्त होना पसंद करते हैं, वहां पेंशन की आयु को 62 से 64 करने के प्रस्ताव का तीखा विरोध हुआ। सिंगापुर में हाल ही में सेवानिवृत्ति की आयु को 63 से 64 वर्ष कर दिया गया और दोबारा नौकरी की आयु को 68 से 69 वर्ष किया गया। इनमें से अधिकांश देश तेजी से बूढ़ी होती आबादी के हिसाब से समाधान कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत में युवाओं की बेरोजगारी का स्तर ऊंचा है और कुशल युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कार्यस्थलों पर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने तथा बुजुर्ग कामगारों के अनुभव से अधिकतम लाभ लेने की विरोधाभासी नीति को अपनाया लाभदायक हो सकता है।

राजनीतिक फलक पर चंद्रशेखर आजाद का उभार

वह बोर्ड जहां से चंद्रशेखर आजाद की यात्रा शुरू हुई थी वह आज भी अपनी जगह पर लगा हुआ है। आजाद उत्तर प्रदेश की नगरीना लोक सभा सीट से सांसद बन चुके हैं। इस बोर्ड में गर्व के साथ लिखा गया है, 'दा ग्रेट चमार डॉ. भीमराव अम्बेडकर गांव घड़कौली आपका अभिनन्दन करता है। सहरनपुर के निकट स्थित घड़कौली गांव में ब्राह्मणों और राजपूतों के अलावा बड़ी तादाद में दलित-चमार और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। गांव को दा ग्रेट चमार गांव बताने वाला बोर्ड 2016 में लगाया गया था। गांव के उच्च जातियों के लोगों ने इस पर आपत्ति की थी। दलितों ने इसे हटाने से मना कर दिया था। दोनों जातियों के बीच बातचीत विफल रही और एक दिन इस बोर्ड को बिगाड़ दिया गया। उस समय चंद्रशेखर आजाद मोटरसाइकिल सवारों के दस्तों के साथ 'जय भीम' और 'जय भीम आर्मी' के नारे बुलंद करते हुए पहुंचे। तनाव बढ़ा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके और जांच के लिए भेजे गए पुलिसकर्मियों तक को घसीट दिया गया। इसके साथ ही सीधे टकराव वाली दलित राजनीति का दौर शुरू हुआ जो युवा पीढ़ी ने नहीं देखा था। उसी महीने राजपूत राजा महाराणा प्रताप के जन्मदिवस के अवसर पर जिले में और अधिक ठाकुर-दलित झड़पें हुईं। राज्य सरकार ने आजाद की भीम आर्मी को हिंसा भड़काने का दोषी माना। आजाद ने दावा किया कि सरकार उस आंदोलन को मलिन करने के लिए उसे निशाना बना रही है और ऊंची जातियों के अपराधियों को बचा रही है। राज्य प्रशासन ने आजाद को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायालय में पहुंचा और उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। परंतु इसके कुछ ही घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दोबारा गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। नागरिक अधिकार समूहों के भारी विरोध के बीच उन्हें दोबारा जेल में डाला गया और इसी दबाव में उन्हें छोड़ा भी गया। जेल से बाहर आने के बाद 2020 में आजाद ने आजाद समाज पार्टी का गठन किया और चुनाव लड़ने का इरादा जताया। आजाद समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कड़े प्रतिरोध के बीच 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी ने भी उसका विरोध किया क्योंकि उसे अपने किले में संध लगती नजर आ रही थी। आजाद ने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन 4,000 से थोड़े अधिक मतों के साथ वह चौथे स्थान पर रहे। परंतु इन बातों ने उन्हें राजनीतिक परिदृश्य पर स्थापित कर दिया। जब वह जेल और अस्पताल में थे तब प्रियंका गांधी ने उन्हें फोन किया। आजाद ने इस सत्ताह के आरंभ में घोषणा की कि वह इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे। उनकी इस घोषणा को उस दौर में बने संबंधों की परिणति माना जा सकता है।

चंद्रशेखर आजाद का जन्म सहरनपुर के घड़कौली गांव में एक चमार परिवार में हुआ था। उन्होंने ठाकुर समुदाय द्वारा संचालित एक कॉलेज में अध्ययन किया और दलित छात्रों के साथ भेदभाव को करीब से देखा। उन्होंने इस्ते लड़ने की ठानी। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उन्होंने आजाद को सलाह दी कि वह अपनी लड़ाई में न्याय के साथ खड़े हों। यह बात अधिक लोग नहीं जानते लेकिन आजाद ने अपना राजनीतिक करियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ शुरू किया था जो भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है। वह अपने साक्षात्कारों में कह चुके हैं उन्होंने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया क्योंकि उन्होंने देखा कि दलितों और मुस्लिमों के बीच लड़ाई में तो भाजपा दलितों का साथ देती लेकिन ऊंची जातियों और दलितों के बीच लड़ाई में वह गायब हो जाती। एक आंबेडकरवादी और कांशीराम (लेकिन मायावती नहीं) के प्रशंसक होने के नाते उन्होंने भी दलितों को एकजुट करने के लिए कांशीराम के ही तौर तरीके अपनाने की ठानी। उन्होंने शिक्षा, अफसरशाही और आत्मरक्षा का मार्ग चुना। आजाद समाज पार्टी की पूर्ववर्ती भीम आर्मी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के दलितों से आग्रह किया कि वे उसके साथ जुड़ें। अधिकांश सदस्य चमार समुदाय या उसकी उपजाति जाटव से हैं लेकिन यहां मुस्लिमों का



सियासी हलचल

आदिति फडणिस

आपका पक्ष

आग से बचाव के लिए सख्त कदमों की जरूरत
आज विज्ञान ने आग बुझाने या आग न लग पाए इसके लिए बहुत से उपाय खोज लिए हैं मगर देश में आग का तांडव जारी है और समय समय पर बड़ी-बड़ी इमारतों में आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। इनमें जान माल की भारी हानि भी होती है लेकिन इससे न तो लोग, न प्रशासन और न ही सरकारें सबक लेती हैं। आग लगने का मुख्य कारण अधिकतर बिजली के शॉर्ट सर्किट को माना जाता है। अधिकतर इमारतों में आपात-कालीन दरवाजे या खिड़कियां भी नहीं होती हैं और दमकल की गाड़ियों का इंतजाम भी समय पर नहीं हो पाता। भविष्य में अगलगी की कोई घटना न हो इसके लिए सरकारों और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। समय समय पर सभी अस्पतालों, मॉल, शिक्षा संस्थानों, कोचिंग संस्थानों आदि सभी इमारतों की जांच करनी चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के प्रति सख्ती



बीते दिनों नई दिल्ली के एक अस्पताल में आग लग गई। हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में आग की यह तीसरी घटना थी

करनी चाहिए और उनकी इमारतों को पब्लिक के लिए तब तक बंद कर देना चाहिए जब तक कि वो आग के कारणों की कमियां दूर नहीं कर लें। अगलगी की घटनाओं से बचाव के प्रति सरकार और

प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए चाहिए जब तक कि वो आग के कारणों की कमियां दूर नहीं कर लें। अगलगी की घटनाओं से बचाव के प्रति सरकार और

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bssmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया



फोटो - पीटीआई

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेन्स्की से अमेरिकी सैन्य सहायता में महीनों की देरी के लिए माफी मांगी। हथियारों की आपूर्ति में देरी के कारण रूस को युद्ध के मैदान में बढ़त हासिल करने में मदद मिली।

भगवानदास छारिया, इंदौर

हमारे जीवन की दूना का निर्धारण हमारी संगति से होता है

राजग सरकार

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं एवं नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए इस गठबंधन को जिस तरह सहज-स्वाभाविक राजनीतिक समूह बताया, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह गठबंधन सरकार चलाने की तैयारी करने के साथ ही देश को यह संदेश भी दे रहे हैं कि ऐसा करते हुए कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। चूंकि अतीत की गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले दलों के मुकाबले इस बार भाजपा के पास कहीं अधिक संख्या बल है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि गठबंधन सरकार का संचालन करने का अनुभव न होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल को आगे बढ़ाने में किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उम्मीद इसलिए भी की जाती है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास सत्ता के संचालन का व्यापक अनुभव है। उनके पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव भले न हो, लेकिन उनके राजनीतिक अनुभव का कोई सानी नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि वह तमाम चुनौतियों के बावजूद बड़े और कड़े फैसले लेने में सक्षम हैं। अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए, जिनमें राज्यसभा में गैर-राजग दलों के सहयोग-समर्थन की आवश्यकता थी। वह अपने राजनीतिक कौशल से यह सहयोग हासिल करने में समर्थ भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह राजग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रकाश सिंह बादल, बाला साहब ठाकरे, जार्ज फर्नांडिस और शरद यादव का स्मरण किया, उससे यह भी संकेत मिलता है कि वह सुखबीर सिंह बादल और उद्धव ठाकरे को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि वे भाजपा के स्वाभाविक सहयोगी हैं। कहना कठिन है कि ये नेता उनके संदेश को सुनने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह विपक्षी दलों को निशाने पर लिया, उससे यह भी पता चलता है कि वह उनके अनुचित दबाव का प्रतिकार करने को तैयार हैं। यह समय ही बताएगा कि विपक्षी दल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार इन खबरों पर कटाक्ष किया कि सहयोगी दलों की ओर से अमुक-अमुक मांगों की जा रही हैं, उससे यही रेखांकित हुआ कि वह इस प्रचलित धारणा को खारिज कर अपनी भावी सरकार की मजबूती बयान करना चाहते हैं कि ऐसी सरकारों को घटक दलों के दबाव की राजनीति का सामना करना पड़ता है। फिलहाल तो सहयोगी दलों के नेताओं और विशेष रूप से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भरपूर सहयोग देने का वादा किया, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि गठबंधन सरकार के कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें इसका अच्छी तरह भान है।

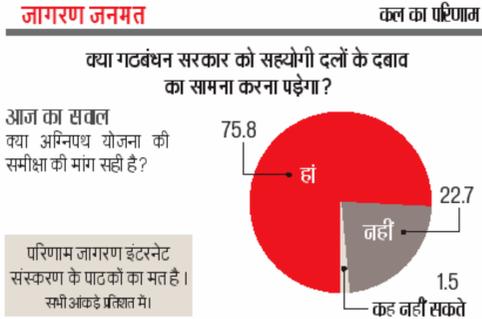
तनाव में काम नहीं होता

राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक इन दिनों छुट्टी पर हैं और उनकी अनुपस्थिति से शिक्षा जगत को काफी रहत महसूस हो रही है। कह सकते हैं कि शिक्षक, छात्र और अभिभावक तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। प्रभार में चल रहे अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ तांबड़तोड़ पाठक के उन आदेशों का संशोधित प्रारूप जारी कर रहे हैं, जिनके चलते शिक्षा जगत में बेचैनी महसूस की जा रही थी। हम यह नहीं कह सकते कि केके पाठक के सभी आदेश तनाव देने वाले ही हैं। उनके कई आदेशों से पठन पाठन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। काम के वरीयता क्रम में पठन-पाठन को नांचे रखने वाले शिक्षकों में सुधार देखा गया है। लेकिन, स्कूलों की समय सारिणी को लेकर हमेशा विवाद ही होता रहा है। शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों का बड़ा काम इनमें काम से अधिक परेशान करने के उद्देश्य को देख रहा है। आप अपने अधीनस्थों से काम लीजिए। यह भी देखिए कि कार्य स्थल पर काम करने के लायक उचित माहौल है या नहीं। शिक्षण ऐसा कार्य है, जिसमें एकाग्रता और मनोयोग की जरूरत होती है। शिक्षक और छात्र प्रतिदिन भारी मन से स्कूल या कालेज पहुँचें तो इसमें पठन पाठन क्या होगा। हाँ ड्यूटी पूरी होगी, जिससे शिक्षकों और छात्रों का कुछ भी भला नहीं होगा। देखना यह होगा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है या नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत इसलिए भी है कि सरकारी स्कूलों में आम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों का एक समूह ऐसा है, जिसे सरकारी स्तर पर शिक्षा न मिले तो पढ़ नहीं पाएँगे। इस को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग को कोई निर्णय लेना चाहिए। यह भी ध्यान में रखा जाए कि राज्य के बजट का करीब बीस प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर ही खर्च होता है।

कह के रहेंगे माधव जोशी



जाब बची तो लाखों पाएँ!!



स्थानीय कारकों ने बिगाड़ा भाजपा का खेल



प्रदीप मेहता

प्रत्याशियों के चयन और सोशल इंजीनियरिंग के मोर्चे पर मिली मत ने भजपा की सीटों की संख्या घटाने का काम किया

नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह एक विशद उपलब्धि है, लेकिन आम चुनाव के परिणाम में भाजपा के लिए अपेक्षा से कुछ कम सीटों ने विश्लेषण को एक नया विमर्श दिया है। भाजपा जहां जीतने के बाद भी चिंतन-मंथन की मुद्रा में है, वहीं विपक्ष हारकर भी उत्साहित दिख रहा है। जिस भाजपा के लिए अपने दम पर सामान्य बहुमत हासिल करना सहज लग रहा था, उसकी गाड़ी बहुमत के आंकड़े से पहले कैसे अटक गई? इस सवाल को पढ़ता करे तो कम से कम 70 ऐसी सीटें रहें, जहां स्थानीय कारकों ने भाजपा के राजनीतिक समीकरण बिगाड़े थे। ये सीटें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा और राजस्थान की हैं। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में गत आम चुनाव में भाजपा को 49.5 प्रतिशत वोट मिले थे, जो इस बार 41.37 प्रतिशत रहे। इसी दौरान बसपा का गठन प्रतिशत भी 19 से घटकर नौ प्रतिशत रह



अक्षय राजपूत

भाजपा अच्छे प्रत्याशियों के अभाव में भुना नहीं पाई। बैरकपुर सीट पर तुणमूल के टिकट से वंचित उम्मीदवार भी भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया, जो हार गया। आसनसोल, दुर्गापुर और मेदिनीपुर की स्थितियां भी अलग नहीं रहीं। लाता है भाजपा ने विधानसभा चुनाव में मिली हार से सबक नहीं सीखा। विधानसभा हारे कई उम्मीदवारों को भाजपा ने लोकसभा का टिकट पकड़ा दिया। इससे मतदाताओं में भरोसा नहीं जाता और मोदी के पक्ष में बने माहौल का लाभ भाजपा उठाने से वंचित रह गई। वहीं, ममता ने सरकारी मशीनरी और प्रशासन के रणनीतिक उपयोग से सत्ता विरोधी रूझान को मात दी। हरियाणा और राजस्थान में भाजपा ने पिछले चुनाव में शत प्रतिशत सफलता हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां घटनाओं की धारा सीटों उसके हाथ से फिसल गई। राजस्थान में नागौर, सौकर, झुंझुनू, चुरू और बाड़मेर में जाट मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी की। टॉक-सबाई माधोपुर और दिसा जैसे सीटों पर भी मांगा समुदाय का भाजपा से मोहभंग

की मुसीबतें बढ़ाने का काम किया। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के वोटों के पूरी तरह से हस्तांतरण को उम्मीद तो पहले से ही थी, लेकिन भाजपा मुंबई और विदर्भ में पिछले चुनाव जैसा करिश्मा नहीं देहरा पाई। भाजपा को अपने सहयोगियों से भी आशातित लाभ नहीं मिला। राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले चुनाव के बराबर ही रहा। दक्षिण भारत में उसे कांग्रेस के मुकाबले अधिक मत मिले। कांग्रेस से सीधे मुकाबले में भी भाजपा का पलट्टा खासा भारी रहा। हालांकि प्रत्याशियों के चयन और उत्तर प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के मोर्चे पर मिली मात ने भाजपा को सीटों की संख्या घटाने में अहम भूमिका निभाई। यदि उसके खिलाफ सत्ता विरोधी रूझान होता तो उसे पिछली बार के लगभग बराबर मत नहीं मिलते। चुनाव परिणाम आने के बाद एनिकेट पोलस की भी निशाने पर लिया गया, लेकिन ऐसा करने वाले जान लें कि इन सर्वेक्षणों में जनता की धारणा के अनुपात में ही आकलन प्रस्तुत किया जाता है। दुनिया भर में एनिकेट पोल कई बार सटीक साबित होते रहे हैं तो कभी कभार गलत हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान बढ़ा। सिरसा सीट पर दलित मतदाताओं ने कांग्रेस को प्रथमिकता दी। यहां पिछले चुनाव में भाजपा को 58 प्रतिशत वोट मिले, जबकि इस चुनाव में 46.11 प्रतिशत। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में जहां पिछले चुनाव में भाजपा को 27.59 प्रतिशत वोट मिले, वहीं इस बार 26.18 प्रतिशत। कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगभग स्थिर रहा, लेकिन उसकी सीटों की संख्या एक से बढ़कर 13 हो गई। यहां भी स्थानीय कारकों ने भाजपा

गठबंधन सरकार की चुनौतियां

देश में केंद्रीय स्तर पर एक बार फिर गठबंधन सरकार की शुरुआत हो गई है। चुनाव में जब कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती तो गठबंधन के माध्यम से सरकार बनाना एक मजबूरी बन जाती है। गुजरात और फिर केंद्र में लगभग ढाई दशक तक बहुमत वाली सरकारों की अनुबाई करने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने जा रहे हैं। नई सरकार में टोटीधी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और जयपू प्रमुख तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मोदी को इस दौरान लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाए रखना होगा। ऐसे में देखना होगा कि उनके नेतृत्व में नई सरकार किस प्रकार के शासन माडल को अपनाती है। भाजपा की योजना प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनकर पूरे देश में शासन नागरिक संहिता लागू करने और सभी प्रकार के चुनाव एक साथ करवाने की थी। गठबंधन सरकार होने के नाते वह देखना रोचक होगा कि भाजपा इन महत्वपूर्ण एजेंडे पर कैसे आगे बढ़ती है?

गठबंधन सरकार होने के नाते वह देखना रोचक होगा कि भाजपा अपने एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाती है?



डॉ. जगदीप सिंह



मंत्रालय में मनमाने करती है और बड़ी पार्टी विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि ऐसा करने पर उसके द्वारा समर्थन वापस लेने का डर रहता है। इस कारण कई बार सरकार को ठंडा और महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पाती। जब सरकार महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेती और केवल सत्ता में बने रहने की कोशिश करती है, तो गठबंधन की राजनीति से उसकी स्थिति कमजोर पड़ जाती है। ऐसी सरकार देश-विदेश से जुड़े मामलों में दृढ़ निर्णय लेने में असमर्थ रहती है। गठबंधन में विभिन्न विचारधाराओं और सिद्धांतों वाले दल शामिल होते हैं, जो कई बार राष्ट्र के बजाय अपने हित साधने वाली नीतियां बनाने की मांग करते हैं। इससे सरकार स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं कर पाती और इसका प्रभाव उसके कार्यों पर पड़ता है। गठबंधन की राजनीति से स्थिरता की भी कमी होती है। देखना होगा कि छोटे दल गठबंधन सरकार पर अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाते रहते हैं। क्षेत्रीय दल अक्सर राष्ट्रीय हितों के बजाय क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे देश के हितों को हानि पहुंचती है। प्रधानमंत्री को अक्सर सहयोगी दलों के दबाव में काम करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें विदेशी समझौतों और संधियों में भी उनकी सलाह लेनी पड़ती है। इससे वैश्विक मामलों में देश की स्थिति कमजोर हो जाती है।

नैस तो देश में 1967 से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी। तब से क्षेत्रवाद के उदय के साथ भारत में गठबंधन अधिारित राजनीति में काफी परिवर्तन आया है। गठबंधन सरकार का देश की व्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो गठबंधन सरकार में एक दल की मंत्रिपरिषद के बजाय कई दलों को मिलकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। जब कई दलों के सदस्यों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है तो इससे अधिक योग्य लोगों की टीम बनती है। इससे सभी दलों के बरिष्ठ सदस्यों की योग्यता का लाभ देश को मिलता है। गठबंधन में शामिल दलों की संख्या जितनी अधिक होती है, सरकार को उतना ही अधिक जन समर्थन प्राप्त होता है। इससे सरकार की स्वीकार्यता भी बढ़ती है। गठबंधन की राजनीति से अतिवादी दृष्टिकोण से भी बचा जा सकता है। एक दल की सरकार जनता पर अपने दृष्टिकोण को थोपने का प्रयास कर सकती है, जबकि गठबंधन में कोई भी दल अकेले अपनी नीतियां और सिद्धांत थोप नहीं सकता, क्योंकि अन्य दल विरोध कर

नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हैं, इस कारण कई अवसरों पर प्रधानमंत्री अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। गठबंधन शासन में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समन्वय की भी कमी देखी जाती है। गठबंधन छोटे राजनीतिक दलों के उदय को भी प्रोत्साहित करता है, जो स्थानीय सरकारों के गठन में एक बाधा है। कुल मिलाकर गठबंधन सरकार का संचालन नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती है। इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ काम करना भी एक बड़ी चुनौती है। ये दोनों नेता अनुभव हैं और अपनी बात मनवाने में सक्षम हैं, जिससे मोदी को दबाव की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजनीतिक प्रगति इसी पर निर्भर करेगी कि वे इस दबाव के बीच कैसे आगे बढ़ते हैं। उनके तीसरे कार्यकाल की सफलता भी इसी पर निर्भर करेगी।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं) response@jagran.com

पाठकनामा
pathaknama@patjagran.com

गठबंधन सरकार की वापसी

‘भाजपा को बदलनी होगी रीति-नीति’ शीर्षक से प्रकाशित अवधेश कुमार का लेख पढ़ा। भाजपा को गठबंधन सरकार चलाने के लिए अब अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने की रीति-नीति अपनानी होगी। दस वर्षों के कार्यकाल में भाजपा के पास खुद का पूर्ण बहुमत था। ऐसे में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो रोडमैप तैयार कर आगे बढ़ जाता था, सभी सांसद कदमताल मिलते हुए उसका समर्थन करते थे, किंतु अब स्थिति बदल गई है। भाजपा को अपने सहयोगियों को खुश रखना होगा। उनके अनुरूप ही रोडमैप तैयार करना होगा, अन्यथा सरकार पर संकेत के बादल कभी भी छा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवस्वत थे कि उन्हें इस बार भी पूर्ण बहुमत मिलेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ, जो भाजपा के लिए निश्चित रूप से बड़ा आघात है। अब मोदी अपने संबोधनों में शब्दचयन का विशेष ध्यान रख रहे हैं। भाजपा की जगह ज्यादा से ज्यादा एनपीए का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से गठबंधन सरकार को ठोक ठोक से चलाने और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन के लिए भाजपा को अपना रीति-नीति में बदलाव करने होंगे। राजनीति में कौन कब और कहां बैठ जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। ऐसे में नेताओं को जनसभाओं और भाषणों में विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने सहयोगियों के प्रति कटुता के ऐसे शब्द मुंह से न निकलें जिससे भविष्य में उन्हें बड़ा नुकसान हो जाए और अफसोस जताना पड़े।

harishtutor1@gmail.com

नई व्यवस्था के तहत भुगतान आवश्यक

‘दूर हो गतिरोध’ शीर्षक से प्रकाशित लेख को पढ़ा। इसे पढ़कर राज्य के विश्वविद्यालयों में चल रही वित्तीय व्यवस्था एवं उसमें व्याप्त संकेत का पता चला। राजभवन सचिवालय द्वारा की जा रही नई वित्तीय व्यवस्था आवश्यक है। जिसके तहत विश्वविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं गैर शिक्षकेतर कर्मचारियों तथा पेंशनरों के वेतन व पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में जमा करने की बात है। यह बदलाव कर्मियों व पेंशनरों के हक में है। अभी की व्यवस्था के अनुसार इनका वेतन भुगतान विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से किया जाता है। हाल के दिनों में राज्य के कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की मनमानी तथा उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायतें मिल रही थीं, इस कारण विश्वविद्यालय कर्मियों के वेतन आदि भुगतान में विलंब होता था। इससे कर्मियों को मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ता था। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस प्रकार के माहौल से उसके विकास में गतिरोध उत्पन्न होता है, जो किसी भी क्षेत्र में नहीं है। इस व्यवस्था के उभरने से उन्हें ससमय वेतन व पेंशन आदि का भुगतान हो सकेगा, जिससे वे निश्चित भाव से जीवन व्यतीत कर सकेगें और मनोयोग से कार्य करेंगे। गत एक वर्ष से शिक्षा विभाग व विश्वविद्यालयों के बीच अधिकारों की लड़ाई के कारण भी व्यवस्थागत कार्यों में गतिरोध बना रहा। इससे विश्वविद्यालयों की छवि को भी नुकसान पहुंचा। ऐसे में कुलपति व कुलालय के अधिकार, कर्तव्य एवं जबाबदाहियों की भी फिर से व्याख्या की जानी चाहिए। ताकि आगे कभी विभाग से टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

डॉ. विकाश कुमार, छपरा, बिहार

पूर्व की नीति पर चलने का संदेश

शिवकांत शर्मा द्वारा लिखित आलेख ‘देश-दुनिया के लिए जनादेश का संदेश’ पढ़ा। लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। भाजपा 240 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई है। एनपीए को जनता ने पूर्ण बहुमत प्रदान किया है, एवं कांग्रेस को मजबूत विपक्ष के रूप में आगे बढ़ने का संदेश दिया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को पूर्व की तुलना में भारी बढ़त मिली है, तो दूसरी ओर एनपीए अपने स्वनिर्धारित चार सौ पार के लक्ष्य से पीछे रह गई है। इस कारण भाजपा की जीत को भी विपक्षी खेमा हार मान रहा है। आश्चर्य का विषय है कि कुछ मीडियकर्मी भी इसे मोदी की पराजय के रूप में देख रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना एक दुर्लभ उपलब्धि है। यह जनादेश नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता की देन है। इससे पूर्व यह प्रदेश में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कर दिखाया था। अपनी नीति पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी को गठबंधन धर्म का पालन करना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने पहले संबोधन में यह स्पष्ट कर दिया है, कि वह सरकार अपने पूर्व की नीति के अनुसार कार्य करेगी। कोई भी सहयोगी दल अकेले सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। मोदी कड़े एवं साहसिक निर्णय के लिए जाने जाते हैं। विपक्षी दलों को मजबूती के साथ सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए।

ई हिमांशु शंकर, कैसपा, गया

चिंतन

नई उम्मीदों-चुनौतियों से भरा होगा मोदी 3:0 कार्यकाल

भारत नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के नेता सर्वसम्मति से चुने गए हैं। अब वे 9 जून रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ मोदी 3:0 कार्यकाल शुरू होगा। राजग संसदीय दल के नेता चुने जाने ने भरोसा दिया है कि राजग सरकार के सभी फैसलों में सर्वसम्मति सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा। स्वाभाविक है कि गठबंधन की सरकार रहने के चलते पिछले दो कार्यकाल से इस तीसरे कार्यकाल में कार्यशैली अलग होगी। अब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी नोटबंदी जैसे ऐलानिया फैसले नहीं कर सकेंगे। सरकार के फैसलों में कैबिनेट के समावेशी स्वरूप का असर दिखेगा। तीसरे कार्यकाल में जहाँ मोदी के सामने भाजपा के संकलन पत्र में किए गए चुनावी वादे पूरे करने की चुनौती होगी, वहीं सहयोगियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का लक्ष्य भी होगा। हो सकता है मोदी के नेतृत्व वाली नई राजग सरकार एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप कार्य करे। मोदी ने सुशासन, समावेशी विकास, जीवन की गुणवत्ता सुधारने, राज्यों के साथ बेहतर संबंध बनाने, वैश्विक विकास व शांति में भारत के योगदान को बढ़ाने, भारत को पांच साल में पांचवाँ से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने आदि का भरोसा दिया है। टीडीपी अध्यक्ष और राजग के अहम घटक चंद्रबाबू नायडू ने साफ संकेत दिया है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय हितों का संतुलन जरूरी है। यह मोदी के लिए साफ संकेत है। इस बार राजग सरकार को मजबूत विपक्ष का भी सामना करना होगा, राज्यसभा में बहुमत की राह और कठिन होगी। विपक्ष को भी रचनात्मक राजनीति को अंगीकार करना चाहिए और संसद में स्वस्थ बहुमत की परंपरा फिर से शुरू होनी चाहिए। मोदी की नई राजग सरकार के सामने अपने संकलन पत्र में किए गए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन, पीएम सूर्यघर, आयुष्मान भारत, पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू सर्विसेज, स्टार्टअप और टूरिज्म में बेहतर सुधार, 3 करोड़ लखपति दीदी, नारी वंदन अधिनियम, किसान कल्याण, श्री अन्न, नैनी यूरिया और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब, आत्मनिर्भर भारत, अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम, नए एयरपोर्ट हाइवे, मेट्रो, अंडरवाटर मेट्रो का निर्माण, भारत स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाइकल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनने जैसे वादे पूरे करने की चुनौती होगी। समान नागरिक संहिता और एक देश, एक चुनाव जैसे एजेंडे भी सामने होंगे। कृषि, श्रम, उर्वरकों और बिजली पर सब्सिडी में सुधार के कदम उठाए जाने हैं। पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाना है। कुछ पीएसयू बैंकों का निजीकरण, संसदीय सीटों का परिसीमन और जनगणना जैसे अहम काम भी करने होंगे। जाति जनगणना, एएसवी व ओबीसी कोटे में फुल्टाइम अवकाश, समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे नेपथ्य में रखे जा सकते हैं। विधानसभा व लोकसभा में महिला आरक्षण भी लागू किया जाना है, परिसीमन के बाद लागू करने की बात है। मोदी की नई राजग सरकार में अब सरकार व घटक दलों के बीच संवाद को प्राथमिकता देनी होगी। आर्थिक सुधार के अगले चरण में भी प्रवेश किया जाना है। नई सरकार जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेगी।

सारा संसार



कनिष्क पद विनायक मंदिर आंध्र प्रदेश के विट्ठल जिले में विरूपित से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित भारत के प्राचीन गणेश मंदिर में से एक है, जो अपनी ऐतिहासिक संरचना और आंतरिक डिजाइन के लिए जाना जाता है।

आवश्यक

डॉ. मोनिका शर्मा



ईवीएम पर सवाल से पहले सोचें

आठवाँ लोकसभा चुनावों में बहुत से जनप्रतिनिधियों में ईवीएम की विश्वसनीयता और केंद्रीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर बार-बार सवाल उठाए। लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभा के लिए प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया। किसी ना किसी दल के लोग चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर आशंका जताते रहते हैं। आरोपों और उल्लाहों का यह खेल हर बार खेला जाने लगा है। आक्षेपों और आरोपों को किसी पुख्ता सबूत के साथ सामने लाने के बजाय अफवाह फैलाने का ही काम किया जाता है। असल में स्वायत्त संवैधानिक निकाय की कार्यप्रणाली पर चूं प्रश्नचिह्न लगाया देश की आम जनता को भी भय और भ्रम के घेरे में लाने वाला बर्ताव है। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने भी सख्ती से कुछ प्रश्न किए हैं। दुखद है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर उठाए जाने सवाल जनता अपने पक्ष में आने के बाद सुनाई नहीं देते, जिसका सीधा सा अर्थ है कि निराधार शिकायतों से केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान शंका का माहौल बनाने वाले जन-प्रतिनिधि परिणामों का रूझान देखकर ही सुर बदल लेते हैं। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग 2024 के आम चुनावों के परिणाम घोषित किए जाने पहले ही स्पष्ट कहा था कि जन-प्रतिनिधि किसी भी तरह की गड़बड़ी के साक्ष्य सामने रखें तो जरूर कार्रवाई की जाएगी, वरना अफवाहों का कोई इलाज नहीं है। समझना मुश्किल नहीं कि चरम मौसमी स्थितियों और बड़ी आबादी वाले भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना आसान काम नहीं है। दुनियाभर में भारतीय चुनाव आयोग के नवाचारों और प्रबंधों को सराहा जाता है। बावजूद इसके आधारहीन आरोप लगाने की स्थितियों के लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, 'हम पर झूठे आरोप लगाए गए। हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में मतदान का विश्व रिकॉर्ड बन गया। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हमने फेक न्यूज रोकी, लेकिन खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए। ध्यातव्य है कि पहली बार निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बातें सामने रखी हैं। 1952 से लेकर अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग द्वारा मतदान के बाद और परिणाम घोषित किए जाने से पहले कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। ऐसे में प्रश्न उठाने वाले राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के प्रश्नों का भी जवाब देना चाहिए। चिंतनीय है कि कभी ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप तो कभी निर्वाचन आयोग पर पक्षपात करने के सनसनीखेज आरोप लगाकर चुनाव प्रणाली का उपहास बनाया जाता है, जबकि अब आम जनता भी यह प्रश्न करने लगी है कि किसी दल की अपनी जीत या बेहतर प्रदर्शन करने पर ईवीएम मशीन को लेकर कोई शिकायत क्यों नहीं रहती? लोकसभा चुनाव-2024 में भी बार-बार ईवीएम के साथ छेड़खानी के आरोप लगाए गए। चुनाव आयोग के हर काम में मीनमेथेक निकालने का रुख अपनाया गया। निर्वाचन आयोग की कोशिशों को सराहने के बजाय हर बार कटघरे में खड़ा करने का ही बर्ताव सामने आया। शोर मचाने वाले दल और जन-प्रतिनिधि जनादेश मिलने पर चुप्पी साध लेते हैं। लोकतंत्र में नेताओं के आधारहीन असंतुष्टि के इस व्यवहार का दोहराव वाकई चिंतनीय है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)



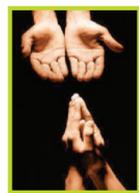
आम चुनाव

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

आम चुनाव परिणामों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि मतदाता के मन को समझना इतना सरल, इतना आसान नहीं है। इसी तरह से एक्जिट पोल और धरातलीय परिणामों में अंतर से साफ हो जाता है कि मतदाता खुलता भी नहीं है तो किसके पक्ष में मतदान करके आया है उसे वह मुखर होकर बताता भी नहीं है। चुनाव परिणामों से सट्टा बाजार की भी पोल खुल कर रह गई है। ऐसे में सवाल यह हो जाता है कि मतदाता इस जनादेश के माध्यम से आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव परिणामों से यह तो साफ हो गया है कि मतदाता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को तीसरी बार सरकार चलाने या यों कहें कि कंटिन्यूटी का अवसर दे दिया है, क्योंकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। ऐसा नहीं है कि परिणाम के बाद किसी बाहरी दल के सहयोग की आवश्यकता हो। बहुमत के 272 की तुलना में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं वहीं पिछले दो चुनावों की तरह इस बार भाजपा को अकेले स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से दूर अवश्य रखा है, पर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सामने आई है। देखा जाए तो 10 साल बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इससे यह भी तो स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता विरोधी लहर उठनी नहीं रही जितनी दस साल के शासन के बाद सामान्यतः आ जाती है, पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आदि के माध्यम से मतदाता ने अपनी नाराजगी जाहिर करने में किसी तरह का संकोच भी नहीं किया है। दरअसल जनआकांक्षाओं और सरकार की परफॉरमेंस के बीच अंतर को पाटने में सरकार पूरी तरह से सफल नहीं रही। हालांकि परफॉरमेंस के पैरामीटर या यों कहें कि मापदंड बदलते रहते हैं। एक बात यह भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यह जनादेश केन्द्र सरकार की वर्तमान नीतियों का नकार नहीं है, अपितु मतदाता सरकार द्वारा नेपथ्य में डाले हुए विषयों को सामने लाकर आगे बढ़ने की दिशा में दिया गया संदेश है और इस जनादेश से एकदम साफ संदेश है कि सरकार की प्राथमिकता में इन विषयों को लेना ही होगा।

दरअसल जनता कहीं ना कहीं संतुलन चाहती है। सरकारों को जहाँ एग्जिट होना अच्छा लगता है वहीं जनता कहीं ना कहीं डिलीवरी सिस्टम को लेकर भी चिंतित रहती है। केवल उज्वल और एग्जिटिव छवि, सफल विदेश नीति, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, धर्म, आर्थिक विकास या यों कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही बहुत से ऐसे कारक हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता।

क्षमा करें और मूल जाएं



संकलित

दर्शन

जीवन में हमें कई बार चुनौतियों और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में हमारा किसी न किसी ऐसी घटना से साक्षात्कार होता है, जो हमें पसंद नहीं होती या जिसके कारण हमें दुख होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने हमारा किसी तरह अनुचित किया हो, शब्दों से हमें भावनात्मक रूप से दुख पहुंचाया हो या शारीरिक कष्ट पहुंचाया हो। परिणाम यह होता है कि हम निराश, दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते, तब तक हमारे साथ क्या होता है? हम हमेशा उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं या किसी और से भी उन बातों को दोहराते रहते हैं। कुछ लोग जिनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता, वे शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं या अपना क्रोध किसी और पर निकालते हैं। ऐसा होने पर हम अपने चारों ओर नकारात्मक वातावरण पैदा कर लेते हैं। अपने मन की शांति खो देते हैं। कुछ क्षणों में घटित हुई घटना के लिए हम अपने जीवन के तमाम घंटे इस बात में लगा देते हैं कि उसका बदला कैसे लें। यदि हम इसके बजाय क्षमा कर दें तो हम इस समय का शांतिपूर्वक सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपना ध्यान उस ओर लगाएँ, जो आध्यात्मिक रूप से मददगार हो। जैसे पिता-परमेश्वर को याद करना, ध्यान-अभ्यास करना, निष्काम सेवा करना और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना। आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान-अभ्यास में सफलता अपने मन को स्थिर करके अंतर में ध्यान टिकाने पर निर्भर है।

अंतर्मुख



करंट अफेयर

फ्रांस यूक्रेन को मिराज लड़ाकू विमान देगा

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि फ्रांस यूक्रेन को रूस के आक्रमण के खिलाफ देश की रक्षा में मदद करने के लिए अपने मिराज लड़ाकू विमान प्रदान करेगा। उन्होंने यह बात डी-डे आक्रमण को स्मरण करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की के फ्रांस में विश्व नेताओं के साथ शामिल होने के बाद की। फ्रांस को नाजियों के कब्जे से छुड़ाने के लिए छह जून, 1944 को नॉरमंडी नामक स्थान पर लड़ाई शुरू हुई थी। छह जून को फ्रांस में 'डी-डे' के तौर पर मनाया जाता है। जेलेन्स्की पश्चिमी देशों से अधिक मदद लेने के लिए फ्रांस में थे जबकि उनकी सेना पूर्वी शहर खारकोव के निकट रूसी हमले को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। मैक्रॉन ने फ्रांसीसी सार्वजनिक प्रसारक को बताया कि वह शुक्रवार को यूक्रेन के साथ नए एनडीए और फ्रांसीसी निर्मित लड़ाकू विमान मिराज 2005 की बिस्की की घोषणा करेंगे जिससे यूक्रेन को रूसी हमलों के खिलाफ अपनी धरती और अपने हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेनी पायलटों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर देगा।



लोकसभा के जनादेश के मायने

आठवाँ लोकसभा के चुनाव परिणामों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि मतदाता के मन को समझना इतना सरल, इतना आसान नहीं है। इसी तरह से एक्जिट पोल और धरातलीय परिणामों में अंतर से साफ हो जाता है कि मतदाता खुलता भी नहीं है तो किसके पक्ष में मतदान करके आया है उसे वह मुखर होकर बताता भी नहीं है। चुनाव परिणामों से सट्टा बाजार की भी पोल खुल कर रह गई है। ऐसे में सवाल यह हो जाता है कि मतदाता इस जनादेश के माध्यम से आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव परिणामों से यह तो साफ हो गया है कि मतदाता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को तीसरी बार सरकार चलाने या यों कहें कि कंटिन्यूटी का अवसर दे दिया है, क्योंकि एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। ऐसा नहीं है कि परिणाम के बाद किसी बाहरी दल के सहयोग की आवश्यकता हो। बहुमत के 272 की तुलना में एनडीए को 293 सीटें मिली हैं वहीं पिछले दो चुनावों की तरह इस बार भाजपा को अकेले स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से दूर अवश्य रखा है, पर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सामने आई है। देखा जाए तो 10 साल बाद किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इससे यह भी तो स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता विरोधी लहर उठनी नहीं रही जितनी दस साल के शासन के बाद सामान्यतः आ जाती है, पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा आदि के माध्यम से मतदाता ने अपनी नाराजगी जाहिर करने में किसी तरह का संकोच भी नहीं किया है। दरअसल जनआकांक्षाओं और सरकार की परफॉरमेंस के बीच अंतर को पाटने में सरकार पूरी तरह से सफल नहीं रही। हालांकि परफॉरमेंस के पैरामीटर या यों कहें कि मापदंड बदलते रहते हैं। एक बात यह भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यह जनादेश केन्द्र सरकार की वर्तमान नीतियों का नकार नहीं है, अपितु मतदाता सरकार द्वारा नेपथ्य में डाले हुए विषयों को सामने लाकर आगे बढ़ने की दिशा में दिया गया संदेश है और इस जनादेश से एकदम साफ संदेश है कि सरकार की प्राथमिकता में इन विषयों को लेना ही होगा।



रही ही नहीं है, अपितु दिन प्रतिदिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना ही एकमात्र काम रह गया। मानो या ना मानो पर आज हालात यह हो गए हैं कि राजनीतिक शालीनता तो रही ही नहीं। दूसरी बात धर्म की करें तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार और यूपी के परिणाम बीजेपी के लिए घोर निराशाजनक होने से साफ संकेत हैं कि केवल श्रीराम लला या धर्म के नाम पर ज्यादा दिन नहीं चला जा सकता। लोगों का मानना है कि अब राम मंदिर बन गया वह सबके सामने हैं तो अब उसे जनमानस की आस्था का केन्द्र रहने दो न कि उसे राजनीतिक रूप से धुनासा। हिन्दी बेल्ट के परिणाम इसे साफ कर देते हैं। लोग आतंकवादी गतिविधियों व अस्माजिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कदम को तो उचित मानते हैं, पर अब इसमें धर्म का प्रयोग कुछ अति ही लगाने लगा है। एक अन्य बिंदु आर्थिक एजेंडा को लेकर है। कहीं भी मतदाता ने आर्थिक एजेंडे को नकारा नहीं है, पर लोग अब महंगाई से त्रस्त हो रहे हैं तो बाजार पर सरकार का नियंत्रण कम होने से परेशान हैं। जनमानस जहाँ आर्थिक क्षेत्र में हाई ग्रोथ चाहने लगा है तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार के अवसरों को लेकर है। पक्ष व विपक्ष सभी का

भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं



संकलित

प्रेरणा

एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन भजन कीर्तन स्मरण सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा- भाई! मैं तो हूँ संसारी आदमी हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपए मेरी ओर से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से सौ रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। वह श्री जगन्नाथ पुर्ण पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्त हरि, वैष्णव जन, हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। भक्त भी वहीं रुक कर जिन मन संकीर्तन का आनंद लेने लगा। उसने सोचा क्यों ना सेठ के सौ रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूँ। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास दो रुपए बच गए उसने सोचा चलो अच्छा हुआ दो रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और अंत में उसने सेठ के दो रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए। भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपए स्वीकार है जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए और उस दो रुपए का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नगद चढ़ाए गए।



शिक्षा में गुणात्मक बदलाव

मेरे जीवन का हर पल भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित है। वे हमारा संविधान ही है, जिससे पिछले परिवार ने पैदा हुए मुझ जैसे व्यक्ति को राष्ट्रसेवा का अवसर मिला है। वे हमारा संविधान ही है, जिसकी वजह से आज करोड़ों देशवासियों को गरिमापूर्ण जीवन मिल रहा है।



-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

इतिहास लिखा जाएगा

जब अब से वर्षों बाद हमारे समय के बारे में इतिहास लिखा जाएगा, तो आपसे हमें यह पीढ़ी होने जितने अपने समय में लोकतंत्र को बढ़ाया। हमारा लोकतंत्र उतना ही मजबूत है जितना हम सब मिलकर इसे मजबूत बनाते हैं।



-ओ बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति

आहार शुचिता आवश्यक

रोगों की प्रायः अनिद्वितीय आहार विहार के कारण होती है। आहार का संबंध मनुष्य के मन से है। शास्त्र और वैज्ञानिकों के अभिराम के अनुसार विना आहार शुचिता के स्वस्थ जीवन संभव नहीं है। अतः सभी के लिए सम्पूर्ण पोषण सुनिश्चित करना समाज और सरकारों का उत्तरदायित्व है।



जांच होनी चाहिए

पेपर लीक, घाघरी और बाटवारा नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गई है। इसका निरोधक नीट्टी स्पष्टकरी की है। वे अर्थव्यवस्था के अविषय से खिलवाड़ है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच होनी चाहिए।



-मलिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष

आपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरपारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फेसबुक : 0771-4242221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

<https://t.me/AllNewsPaperPaid>

<https://t.me/AllNewsPaperPaid>

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid

2. आकाशवाणी (AUDIO)

3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

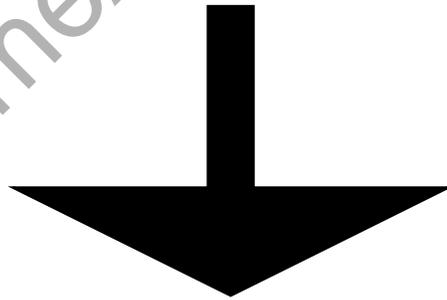
Type in Search box of Telegram

@AllNewsPaperPaid And you will find a Channel

Name All News Paper Paid Paper join it and receive

daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:



<https://t.me/AllNewsPaperPaid>

<https://t.me/AllNewsPaperPaid>

<https://t.me/AllNewsPaperPaid>